

Chief Minister's Information System CM Directions

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
1	दिनांक 30.09.2015 को आयोजित जिला सवाई माधोपुर की समीक्षा बैठक के दौरान।	स्वच्छ भारत अभियान में जन प्रतिनिधियों को भी सक्रिय सहयोग करने के निर्देश दिये गये।	जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षणों एवं अभियानों में जिले के जन प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जिला कलक्टर एवं सहअध्यक्ष, सवाई माधोपुर को पत्र दिनांक 26.10.2015 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
2	Review Meeting of Individual Beneficiary Schemes dated 16.10.2015.	A letter from Chief Secretary to low performing Collectors in ODF. Timeline - 23.10.2015	मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान योजनान्तर्गत कम प्रगति वाले जिलों के जिला कलक्टरों यथा बांसवाडा, बाडमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड, कोटा, करौली, प्रतापगढ, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, एवं उदयपुर को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 30.10.2015 द्वारा लिखा गया है।	Implemented
3	Instructions given by Honble Chief Minister on 29.10.2015 at Nagaur.	To devise a mechanism to convert waste in Swachh Bharat Abhiyaan into organic manure.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत समस्त जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उक्त निर्देशों के क्रम में पत्र द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यों की डीपीआर में उक्त गतिविधि को शामिल किया गया है।	Implemented
4	Instructions given by Honble Chief Minister on 29.10.2015 at Nagaur.	To identify a site for use as dumping yard in all big villages	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत समस्त जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यों के अन्तर्गत डम्पिंग यार्ड का चिन्हकरण किया जा रहा है।	Task Started, but not Completed
5	Instructions given by Honble Chief Minister on 30.10.2015 at Nagaur.	To try community toilets first in urban areas and later in rural areas.	उक्त निर्देशों के क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत समस्त जिलों के कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र दिनांक 10.11.2015 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
6	Instructions given by Honble Chief Minister on 30.10.2015 at Nagaur.	To fill-up 4 vacant posts of BDO.	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 62 विकास अधिकारियों को चयनित किया गया है। जिसमें से 54 विकास अधिकारियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण पश्चात विभागीय आदेश दिनांक 01.06.2016 को पदस्थापित किये जा चुके हैं। उक्त आदेशों द्वारा नागौर जिले में 3 पंचायत समितियों पर विकास अधिकारी पदस्थापित कर दिये गये हैं।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
7	बाड़मेर विजिट के दौरान दिनांक 23.10.2015 को जनप्रतिनिधियों से चर्चा में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर।	बायतू में पंचायत समिति प्रधान के विरुद्ध तीन संतान होने की शिकायत है जिसमें आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसकी जांच की जाए।	बायतू में पंचायत समिति प्रधान के विरुद्ध तीन संतान होने की शिकायत की जांच जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा सही पाये जाने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 व 39 के तहत संबंधित को विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2015 को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।	Implemented
8	बाड़मेर विजिट के दौरान दिनांक 23.10.2015 को जनप्रतिनिधियों से चर्चा में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर।	जिले में विकास अधिकारी का पद रिक्त है, शीघ्र पदस्थापन किया जाए।	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 62 विकास अधिकारियों को चयनित किया गया है। जिसमें से 54 विकास अधिकारियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण पश्चात विभागीय आदेश दिनांक 01.06.2016 को पदस्थापित किये जा चुके हैं। उक्त आदेशों द्वारा बाड़मेर जिले में 6 पंचायत समितियों पर विकास अधिकारी पदस्थापित किये जा कर सभी रिक्त पद भर दिये गये हैं।	Implemented
9	बाड़मेर विजिट के दौरान दिनांक 23.10.2015 को जनप्रतिनिधियों से चर्चा में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर।	नवगठित पंचायत समितियों एवं पंचायतों के भवन निर्मित करने हेतु वित्तीय राशि स्वीकृत की जाए।	47 पंचायत समितियों में से 45 पंचायत समिति भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जा चुकी है। पंचायत समिति समदडी (बाड़मेर) एवं चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर) के लिये पुराने स्कूल भवन उपलब्ध है। 45 पंचायत समितियों में से 28 पंचायत समितियों को भूमि आवंटन हो गयी है। वित्त विभाग द्वारा 28 पंचायत समितियों के निर्माण हेतु 14 करोड की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।	Implemented
10	Instructions of Hon'ble Chief Minister during Field Inspection on 24.10.2015 at Barmer.	Scrap worthy vehicles lying with various departments and their disposal- Detailed inventory and action plan to be drawn up	जिला परिषद बाड़मेर में 2 वाहन नकारा अवस्था में थे जिनके निस्तारण हेतु कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 22.06.2016 को निलामी द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। एवं निलामी से प्राप्त संपूर्ण राशि राज कोष में जमा कर दी गयी है।	Implemented
11	दिनांक 25.10.2015 को बाड़मेर विजिट में जिला अधिकारियों की बैठक के दौरान।	जनता जल योजनाओं का संधारण पंचायतों के माध्यम से करवाया जावे।	आदेश दिनांक 30.03.2015 के द्वारा जनता जल योजनाओं के समस्त व्यय का भुगतान अनुदान राशि से करने के आदेश जारी। दिनांक 22 जनवरी, 2016 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जनता जल योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जाने एवं योजनाओं के	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
			प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य स्तर पर आवश्यक कार्मिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराये जाने बाबत मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 15/2016 दिनांक 05.02.2016 को जारी की गई है।	
12	दिनांक 25.10.2015 को बाड़मेर विजिट में जिला अधिकारियों की बैठक के दौरान।	जिला परिषद की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करवाई जावें।	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 47 के अनुसार जिला परिषद की बैठकें प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित करवाये जाने हेतु पत्र दिनांक 27.11.2015 द्वारा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। निर्देशों की पालना अविलंब किये जाने हेतु संबंधित जिले/अनुभाग को अशा टीप प्रेषित कर दी गई है।	Implemented
13	दिनांक 25.10.2015 को बाड़मेर विजिट में जिला अधिकारियों की बैठक के दौरान।	जिले में रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जावें।	बाड़मेर जिले में सभी 6 पंचायत समितियों में रिक्त चल रहे पदों पर विकास अधिकारी पदस्थापित कर दिये गये हैं।	Implemented
14	दिनांक 25.10.2015 को बाड़मेर विजिट में जिला अधिकारियों की बैठक के दौरान।	जिले में सफाई का विशेष अभियान चलाया जावें। शहर एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों में कचरा डालने हेतु स्थान चिन्हित किये जावे वहाँ पर ही कचरा डाला जावे।	मा0 मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना में बाड़मेर जिले में साफ-सफाई का विशेष अभियान दिनांक 01.12.15 से 15.12.15 तक चलाया गया जिसके तहत कार्यालय की साफ-सफाई, रंग रोगन, आसपास के क्षेत्र के बबूल कटाई, मलबे एवं गंदगी के ढेर हटाना आदि कार्य किये गये। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित नारा लेखन व होर्डिंग लगाये गये एवं सफाई व्यवस्था एवं कचरा डालने हेतु स्थान चिन्हित कर कचरा इकट्ठा करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
15	District Collectors and Superintendents of Police Conference on July 22 & 23, 2015 under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister.	There are number of issues relating to the Janta Jal Yojana consequent to the transfer of the scheme from the PHED to the Panchayat Raj Department. These issues need to be	इस विषय में दिनांक 04.11.2015 को मा0 मंत्री महो0 ग्रा.वि. एवं पं राज विभाग एवं मा0 मंत्री महो0 पी.एच.ई.डी. के अध्यक्षता में मुख्य सचिव एवं संबंधित अधिकारियों को आमंत्रित कर एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पेयजल योजनाओं का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाये इस पर निर्णय हेतु पंचायती	Implemented

Chief Minister's Information System CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		highlighted by the Panchayat Raj Department and a meeting proposed with the PHED at the level of the Chief Secretary.	राज द्वारा मंत्रीमण्डल जापन प्रस्तुत कर निर्णय मंत्रीमण्डल से कराने का निर्णय लिया गया।	
16	District Collectors and Superintendents of Police Conference on July 22 & 23, 2015 under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister.	District Collector, Jaipur advocated that linkage between Revenue and Panchayat Raj bodies should improve at the SDO level. At present the SDO has virtually no role in Panchayat Raj. He should be assigned the task of supervision of Panchayats for which enabling provisions should be put in place. Panchayat Raj Department may examine the issue.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के स्तर के एवं समकक्ष अधिकारी होते हैं, जिनकी चयन प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण भी राजस्थान राज्य सेवा के समान ही है। पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु अलग से पूर्ण चैनल निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति का अध्यक्ष होता है, जिसके पदीय कर्तव्यों में उसे खण्ड स्तरीय समस्त कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण एवं मोनिटरिंग की शक्तियां प्रदत्त की हुई हैं। इसलिए उपखण्ड अधिकारी को पंचायती राज संस्थाओं के पर्यवेक्षण का कार्य दिया जाना प्रशासनिक एवं व्यावहारिक रूप से सही प्रतीत नहीं होता है।	Implemented
17	District Collectors and Superintendents of Police Conference on July 22 & 23, 2015 under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Minister.	Swachh Bharat Abhiyan, has been accorded highest priority and Collectors should, therefore, devote their time and energy towards making this Abhiyan a success. In the scheme one Village in the Panchayat, one Panchayat in the Panchayat Samiti and one Panchayat Samiti in a District should be suitably incentivized by District Collectors.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को गोद लेकर कार्यक्रम को गति देने में अपनी भागीदारी निभाने हेतु समस्त जिला कलेक्टरों को शासन सचिव एवं आयुक्त की ओर से पत्र दिनांक 23.11.2015 को प्रेषित कर दिया गया है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
18	झालावाड़ प्रवास के दौरान दिनांक 22 से 24.12.2015 को ली गई समीक्षा बैठक में।	जिला झालावाड़ एवं बारां की पंचायती राज संस्थाओं में स्वच्छ भारत मिशन की राशि शीघ्र भिजवायी जाये तथा उपलब्ध शेष बजट का शीघ्र उपयोग किया जाये।	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला झालावाड़ को राशि रुपये 60.25 करोड एवं जिला बारां को राशि रुपये 48.81 करोड का आवंटन कर दिया गया है। जो इस वित्तीय वर्ष की मांग के अनुसार पर्याप्त है।	Implemented
19	Aide Memoires of Review Meeting of Rural Development and Panchayati Raj Department dated 18.02.2016.	Swachh Bharat Mission - Illrd party verification of toilets and other assets. Plan for water in toilets (especially in case of institutions) - Promote force and lift hand Pumps.	Directions had been issued to all District Collectors and CEOs on 21-03-2016 for Illrd party verification of toilets and other assets. For promoting force and lift hand Pumps a letter dated 21-03-2016 had been issued to ICDS & School Education Department.	Implemented
20	Aide Memoires of Review Meeting of Rural Development and Panchayati Raj Department dated 18.02.2016.	Note on requirement of funds under Swachh Bharat Mission.	Note on requirement of funds under Swachh Bharat Mission has been sent to CMO on 22-03-2016.	Implemented
21	Aide Memoires of Review Meeting of Rural Development and Panchayati Raj Department dated 18.02.2016.	Application for PR Department (including accounting).	ईटिग्रेटेड राज ई-पंचायत सॉफ्टवेयर दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रत्येक जिला परिषद, पंचायत समिति एवं प्रत्येक पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत में पायलट आधार पर लागू किया जा चुका है। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर (जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत) से अब तक कुल 447.00 करोड से अधिक का ऑन लाईन भुगतान किया जा चुका है। विभागीय पत्र दिनांक 23.01.2018 के द्वारा जिलों को यह निर्देश दिये गये है कि वर्तमान में सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई पंचायतों के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायत इस सॉफ्टवेयर से राशि भुगतान की कार्यवाही नहीं करें। यदि कोई पंचायत समिति की नवीन ग्राम पंचायत सॉफ्टवेयर से राशि का भुगतान करना चाहती है तो मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करके की जावें।	Task Started, but not Completed

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
22	दिनांक 20-22.4.2016 को झालावाड़ एवं बारां प्रवास के दौरान।	शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों, बिना हेलमेट चलने वाले दुपहिया वाहन चालकों, संपत्ति विरूपण अधिनियम के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति को विरुपित करने के दोषियों एवं आवारा पशुओं (विशेषकर गायों) को छोड़ने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायें	राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय - 8 कॉजी हाउस (CATTLE POUNDS) में नियम 115 से 135 तक के अनुसार आवारा पशुओं (विशेषकर गायों) को छोड़ने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही (आवारा पशुओं पर नियंत्रण रखने तथा इन पशुओं को छोड़ने वाले संबंधित व्यक्ति/ स्वामी से जुर्माना प्राप्त) अमल में लाए जाने बाबत समस्त जिला परिषदों को पत्र दिनांक 27.05.2016 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
23	दिनांक 20-22.4.2016 को झालावाड़ एवं बारां प्रवास के दौरान।	आवारों गायों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की जाये।	राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय - 8 कॉजी हाउस (CATTLE POUNDS) में नियम 115 से 135 तक के अनुसार आवारों गायों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की जाने बाबत समस्त जिला परिषदों को पत्र दिनांक 27.05.2016 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
24	Instruction given by the Honble CM during review meeting at Bhilwara dated 28.06.2016.	The Rural Development & Panchayat Raj Department should carry out an intensive drive for IEC of cleanliness and sanitation in the Panchayat and all villages.	भीलवाड़ा जिले में स्वच्छता पखवाड़े के तहत दिनांक 01 से 15 अक्टूबर 2016 तक स्वच्छता हेतु प्रचार प्रसार कर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है।	Implemented
25	Instruction given by the Honble CM during review meeting at Bhilwara dated 28.06.2016.	Every Panchayat should have a board depicting the amount of funds received under different schemes. This should be updated regularly and the local people should be made aware of these funds by intensive, IEC. So that instead of looking up to the government for every work, the people should ask the	समस्त जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों के बाहर एक सूचना पट्टिका जिस पर वर्ष 2014-15 से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाएं एवं बजट आवंटन का विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार करवाकर प्रदर्शित करने हेतु आदेश दिनांक 22.07.2016 जारी कर दिया गया है। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत मुख्य कार्यों का सार रूप में विवरण देते हुए अटल सेवा केन्द्र पर वॉल पेंटिंग कर प्रदर्शित किया जा रहा है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		Sarpanch and the Ward Panchs for getting their works done.		
26	Instruction given by the Honble CM during review meeting at Bhilwara dated 28.06.2016.	The villagers should be explained in detail the amount of funds being received by Panchayat under different heads and how it can be utilized.	प्रत्येक पंचायत में आयोजित होने वाली हर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आवंटित होने वाली राशि तथा उसके ग्राम वार व वार्डवार व्यय का विवरण ग्राम सभा में ग्रामीण जन को पढकर सुनाने एवं ग्रामीण जन द्वारा उठाई गई शंकाओं के समाधान करने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 22.07.2016 जारी कर दिया गया है। उक्त क्रम में प्रत्येक ग्राम सभा में निर्देशों की पालना की जा रही है।	Implemented
27	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Sirohi -28th -30th July, 2016.	Principal Secretary, RD & PR to get all the works of the Panchayat Jawal inquired in detail.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2016 को राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर जांच करवायी गयी। कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टरया दोषी पाये गये कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच में दोषी पाये गये ग्राम सेवक के विरुद्ध जिला स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दोषी सरपंच के विरुद्ध संभागीय आयुक्त जोधपुर के स्तर से कार्यवाही की जा रही है। जांच में दोषी पाये गये अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, जावल के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13.10.2017 के क्रम में जिला कलक्टर को जिला स्तर पर ही अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र दिनांक 25.01.2018 द्वारा निर्देशित किया गया है।	Task Started, but not Completed
28	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Sirohi -28th -30th July, 2016.	It was also brought to notice that all other Talabs had been encroached. These encroachments should be removed immediately	इस जिले की पंचायत समिति शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड एवं रेवदर के विकास अधिकारियों ने अवगत कराया कि पंचायत समिति क्षेत्र में मॉडल तालाबों में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।	Implemented

Chief Minister's Information System CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
29	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Sirohi -28th -30th July, 2016.	In Angour village the solar lights are not functional due to lack of maintenance. The Gram Panchayat / Panchayat Samiti/ Zila Parishad should arrange for the battery from available funds	In Angour village, all solar lights are operationalized by Gram Panchyat.	Implemented
30	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Sirohi -28th -30th July, 2016.	Focus should not only be on construction of toilets but also their usage. At the same time a system for proper disposal of waste and garbage should be in place in all the Panchayats and urban areas.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित शौचालय का भुगतान लाभार्थी द्वारा उपयोग लिया जाना सुनिश्चित होने पर ही किया जा रहा है। ODF पंचायतो में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्यों के तहत कचरा एकत्रीकरण एवं निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाती है।	Implemented
31	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Sirohi -28th -30th July, 2016.	A detailed audit of sanctions and expenditure under various schemes like - MLALAD, MPLAD, MNREGA, 13th - 14th Finance Commission, State Finance Commission in last 2 years has to be conducted by RD & PR Department in Dodua Gram Panchayat.	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर के जांच दल संख्या 5 द्वारा ग्राम पंचायत डोडुआ, पंचायत समिति सिरोही की विगत दो वर्षों की विस्तृत जांच दिनांक 02.01.2017 से 10.01.2017 तक सम्पादित की जा चुकी है। जांच में दोषी पाये गये ग्राम सेवक के विरुद्ध जिला स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दोषी सरपंच के विरुद्ध संभागीय आयुक्त जोधपुर के स्तर से कार्यवाही की जा रही है। जांच में दोषी पाये गये विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध मुख्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच में दोषी पाये गये पंचायत प्रसार अधिकारी को स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर 17सीसीए में कार्यवाही का निर्णय लिया गया है जिसके लिए जिला परिषद सिरोही से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।	Task Started, but not Completed
32	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Dungarpur -7th -10th August, 2016.	गोगूरा पंचायत में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, जिन्हें जिला कलक्टर एवं विभाग द्वारा हटवाया जाए।	ग्राम गोगूरा के खसरा नं. 725 पर अतिक्रमण बाबत शिकायत प्रस्तुत हुई थी। ग्राम गोगूरा के खसरा नं. 725 किस्मु बिलानाम मगरी पर बदा पुत्र जीवा डोडियार द्वारा करीब 1.10 बीघा भूमि पर जुताई कर अतिक्रमण किया था। उक्त अतिक्रमण हटवा दिया गया है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
33	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Dungarpur -7th -10th August, 2016.	निर्माण कार्यो तथा जिन पंचायतों को ODF घोषित किया गया है। उनका थर्ड पार्टी (स्वतंत्र) से ऑडिट करवाया जाए। जिला कलक्टर इनकी व्यापक जांच सुनिश्चित करें।	जिन पंचायतों को ODF घोषित किया गया है उनका थर्ड पार्टी (स्वतंत्र) से ऑडिट करवाने एवं जिला कलक्टर इनकी व्यापक जांच सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2016 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। जिले के जिला कलक्टर के द्वारा जिले की समस्त पंचायतों के ODF होने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही जिले को ODF घोषित करने की कार्यवाही की जाती है।	Implemented
34	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during visit of Dungarpur -7th -10th August, 2016.	शहर के सौन्दर्यकरण एवं स्वच्छता के अनुरूप शहर से बाहर गांवों में भी सौन्दर्यकरण एवं स्वच्छता की जाए और ऐसी पहल वाले गांवों को प्रोत्साहित किया जाए।	शहर जैसी स्वच्छता हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रा0 एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के डोवटेल से ग्रामीण क्षेत्रों में सौन्दर्यकरण एवं स्वच्छता हेतु नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना लागू की जा चुकी है जिसके तहत गांव को स्वच्छ बनाना, स्वच्छता का वातावरण तैयार करना एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूक करना है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के क्रम में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन घटक से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई हेतु सफाई उपकरण यथा साईकिल रिक्शा मय टोली, सार्वजनिक कचरा पत्र आदि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।	Implemented
35	दिनांक 18 से 20 सितम्बर, 2016 तक दौसा यात्रा के दौरान ।	वाद रहित एवं अपराध मुक्त गांवों के प्रोत्साहन हेतु योजना बनाने के संबंध में ।	वाद रहित एवं अपराध मुक्त गांवों के प्रोत्साहन हेतु योजना बनाने के कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	Task Started, but not Completed
36	दिनांक 18 से 20 सितम्बर, 2016 तक दौसा यात्रा के दौरान ।	गांवों में हैण्डपम्प एवं पी.एस.पी. या मोटर पम्प वाले स्थानों पर एम.जे.एस.ए./नरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सोकपिट बनाने के संबंध में।	गांवों में हैण्डपम्प एवं पी.एस.पी. या मोटर पम्प वाले स्थानों पर एम.जे.एस.ए./नरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सोकपिट बनाने के संबंध में पत्रांक 4828 दिनांक 17.10.2016 द्वारा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और उक्त योजनाओं में साेकपिट बनाये जा रहे हैं।	Implemented
37	दिनांक 18 से 20 सितम्बर, 2016 तक दौसा यात्रा के दौरान ।	जिला कलक्टर ग्राम पंचायत को ODF घोषित करने से पहले स्वयं के स्तर पर रेण्डम	समस्त जिला कलेक्टरों को विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2016 द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे RTGS के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जमा कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		चैकिंग कर ओडीएफ बाबत संतुष्टि करें। इसके साथ लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को बैंक में जमा होते ही जमा होने की सूचना SMS से लाभार्थी को दी जाए।	संबंधित जिले के जिला कलक्टर के द्वारा जिले के समस्त पंचायतों को ODF होने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही जिले को ओडीएफ घोषित करने की कार्यवाही की जाती है।	
38	Review Meeting of District Jhalawar dated 19.10.2016.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम फेज के सभी कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित की जाये एवं द्वितीय फेज के कार्यों की डीपीआर तत्काल प्रस्तुत की जाये।	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम फेज में 96709 स्वीकृत कार्यों में से 95184 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। एवं द्वितीय चरण 9 दिसम्बर 2016 से आरम्भ हो चुका है। द्वितीय फेज के कार्यों की डीपीआर प्रस्तुत की जा चुके हैं।	Implemented
39	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर-2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	पंचायत शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा पम्पलेट्स/ प्रचार सामग्री शिविरों स्थल पर उपलब्ध करायी जावे।	पंचायत शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु राज्य स्तर से पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम 2016 नामक पुस्तिका प्रकाशित करवाकर समस्त जिलों को वितरित की जा चुकी है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी उनके जिले में होने वाले शिविरों की जानकारी सम्मिलित करते हुए पुस्तिका/ पम्पलेट्स/ प्रचार सामग्री प्रकाशित करवाकर उपलब्ध करवायी जा चुकी है।	Implemented
40	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर-2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	पंचायत शिविर की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जावे।	पंचायत शिविर की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
41	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर-2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	पंचायतीराज विभाग पंचायत शिविरों में भाग लेने वाले समस्त विभागों से समन्वय कर प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करें।	पंचायत शिविरों में भाग लेने वाले समस्त विभागों की प्रगति की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सभी 17 विभागों के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों की बैठक आयोजित कर समीक्षा की गयी।	Implemented
42	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर-2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	पंचायत शिविर में सम्मिलित विभागों के विभागाध्यक्ष/शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अपने विभाग के पंचायत शिविर में किये जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रभावी मोनिटरिंग की जावे।	पंचायत शिविर में अपने अपने विभाग के किये जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा करने हेतु समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष/शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव को विभागीय पत्र दिनांक 02.11.2016 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
43	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर-2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा जिलों का दौरा कर पंचायत शिविरों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण/ओडीएफ/साफ-सफाई आदि कार्यों की समीक्षा की जावे।	निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा माह नवम्बर 2016 में डुंगरपुर जिले , फरवरी, 2017 में जोधपुर जिले तथा माह मार्च, 2017 में जिला बांसवाडा का दौरा कर शौचालय निर्माण/ओडीएफ/साफ-सफाई आदि कार्यों की समीक्षा की गयी।	Implemented
44	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय	पंचायत शिविरों में मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई सुनिश्चित की जावे	पंचायत शिविरों में मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने एवं पंचायतों में शिविरों के दौरान हरे रंग का कचरा पात्र रखवाने एवं उन पर लिखावट सफेद रंग की हो बाबत निर्देश दिनांक	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
	जन कल्याण पंचायत शिविर- 2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	तथा पंचायतों में शिविरों के दौरान रखवाये जा रहे कचरा पात्रों का रंग सुनिश्चित किया जावे।	21.10.2016 को जारी किये जा चुके हैं। पंचायत शिविरों में 46376 नवीन कचरा पात्र रखवाये जा चुके हैं। साथ ही 16501.08 किमी सड़कों की सफाई करते हुए 4242.58 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।	
45	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर- 2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण अन्तर्गत अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करवाया जावे तथा अभियान अन्तर्गत सभी कार्यों की जियो टैगिंग करवायी जावे एवं वृक्षारोपण का भौतिक सत्यापन कर उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जावे।	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण में 96709 स्वीकृत कार्यों में से 95184 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा सभी कार्यों की जियो टैगिंग की गयी है। शिविरों के दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत लगाये गये पौधों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।	Implemented
46	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर- 2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	पंचायत शिविरों के दौरान बंद पड़ी जनता जल योजनाओं को चालू करवाया जावे।	पंचायत शिविरों के दौरान बंद पड़ी जनता जल योजनाओं को चालू करवाये जाने बाबत दिनांक 26.10.2016 द्वारा समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी को निर्देशित कर दिया गया है। पंचायत शिविरों के दौरान बंद पड़े 15517 हैण्डिपम्प / ट्यूब वेल ठीक करवाये।	Implemented
47	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर- 2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा पंचायत शिविरों के दौरान किये जाने वाले कार्यों की प्रगति के लिए प्रपत्र निर्धारित कर	समस्त विभागों द्वारा पंचायत शिविरों के दौरान किये जाने वाले कार्यों की प्रगति के लिए प्रपत्र निर्धारित कर पंचायतीराज विभाग को उपलब्ध करवा दिये गये हैं जिन्हें विभाग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		पंचायतीराज विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाये हैं, जिन्हें तत्काल उपलब्ध करवावे तथा पंचायतीराज विभाग प्राप्त प्रपत्रों को अपलोड करावें।		
48	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर- 2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के एकीकरण से खाली हुये भवनों का सूचीकरण कर स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार संबंधित ग्राम पंचायत को कब्जा सुपुर्द कराया जावे।	खाली हुये भवनों में से 8 भवन नवीन ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु उपयोग में लिये जा रहे हैं।	Task Started, but not Completed
49	माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर- 2016 की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश।	पंचायत शिविर में भाग लेने वाले समस्त विभागों द्वारा शिविर में किये जाने वाले कार्यों की तैयारी शिविर आयोजन के पूर्व सुनिश्चित की जावे तथा शिविर के दौरान सक्रिय भागीदारी निर्वहन करें एवं पूर्व के आयोजित शिविरों के कार्यों का फालोअप किया जावे।	अपने विभाग के पंचायत शिविर में किये जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रभावी मोनिटरिंग करने हेतु पंचायत शिविर में सम्मिलित समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष/शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव को विभागीय पत्र दिनांक 02.11.2016 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
50	Collectors Conference 24th - 27th November 2016.	Pendency of sanctions in any of the schemes has to be reduced to minimum.	समस्त जिला कलक्टरों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उक्त निर्देश की क्रियान्विति हेतु दिनांक 13.12.2016 को पत्र लिखा जा चुका है। माह जनवरी, 2017 की जिलों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार पंचायती राज द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं यथा चौदहवां	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
			वित्त अायोग, राज्य वित्त आयोग (पंचम) व निर्बंध राशि योजना (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) अन्तर्गत कुल स्वीकृत कार्यो 140603 में से 91034 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 44337 कार्य प्रगतिरत है। योजनाओं में अप्रारंभ कार्य 5232 है जो शीघ्र प्रारंभ करवाये जा रहे हैं।	
51	Collectors Conference 24th - 27th November 2016.	Status of utilization certificates is to be an essential component of monitoring by Collectors.	समस्त जिला कलक्टरों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उक्त निर्देश की क्रियान्विति हेतु दिनांक 13.12.2016 को पत्र लिखा जा चुका है।	Implemented
52	Collectors Conference 24th - 27th November 2016.	Principal Secretary, Home and Principal Secretary, RD & Panchayat Raj to examine the possibility of evolving a rural model of 'INOX' and other Multiplex. Collector, Kota can be contacted in this regard.	उक्त निर्देशों की क्रियान्विति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही है। अतः उक्तव निर्देश को पंचायती राज की सीएमआईएस से हटाते हुए संबंधित विभाग को हस्तांतरित करवाने का श्रम करावें।	Implemented
53	दिनांक 17.12.2016 को जोधपुर प्रवास के दौरान समीक्षा बैठक में	ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों में प्रभारी अधिकारी एक दिन पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। शिविर स्थल पर संबंधित पंचायत में स्वीकृत मुख्य कार्यो का सार रूप में विवरण देते हुए अटल सेवा केन्द्र पर वॉल पेंटिंग अवश्य की जाए।	सभी जिला कलक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों में प्रभारी अधिकारी को एक दिन पहले पहुंचने तथा शिविर स्थल पर संबंधित पंचायत में स्वीकृत मुख्य कार्यो का सार रूप में विवरण देते हुए अटल सेवा केन्द्र पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करने हेतु पत्र दिनांक 10.01.2017 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा स्वीकृत मुख्य कार्यो का सार रूप में विवरण देते हुए अटल सेवा केन्द्र पर वॉल पेंटिंग कर प्रदर्शित किया जा रहा है।	Implemented
54	जोधपुर मुख्यालय पर दिनांक 19 जनवरी, 2016 को आयोजित बैठक में।	लोरडिया टाउन में वाटर लोडिंग की समस्या का निराकरण किया जाये।	14वां वित्त आयोग अन्तर्गत 10.00 लाख रुपये एवं राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत 2.50 लाख रुपये इस प्रकार कुल 12.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर पंचायत समिति फलोदी, जिला परिषद जोधपुर में लोरडिया टाउन की	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
			वाटर लॉगिंग की समस्या के निराकरण हेतु पानी निकासी के लिए भूमिगत पाईपलाईन का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। वर्तमान में वाटर लॉगिंग की कोई समस्या नहीं है।	
55	Instructions given by Hon'ble CM during Karauli Visit 11 - 13 May, 2017.	All the individual toilets to be constructed by beneficiaries themselves rather than contractors.	Department had already issued directions by order vide no 626 dt. 22-04-2015 & 4157 dt. 12-08-2016 to all districts to all individual toilets to be constructed by beneficiaries themselves rather than contractors.	Implemented
56	Aide Memoires of Review Meetings of Women & Child Development, Rural Development, Panchayati Raj Departments dated 29.05.2017.	Construction of Gram Panchayat buildings - Indicate milestones, upload photos for reality check.	नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण MGNREGS से हो रहा है। कार्यों का पूर्ण विवरण NREGASOFT में online उपलब्ध हैं। NREGASOFT में कार्यों के Photos भी upload किए जाते हैं।	Implemented
57	Aide Memoires of Review Meetings of Women & Child Development, Rural Development, Panchayati Raj Departments dated 29.05.2017.	View needs to be taken regarding transfer of technical staff from PHED for operation and control of Janta Jal Yojana by Panchayat Samities.	मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 05.02.2016 के निर्णयानुसार जनता जल योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जाने एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य स्तर पर आवश्यक कार्मिक पी.एच.ई.डी. द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्रावली अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दि० 17.07.2017 को बैठक आयोजित की गई जिसमें पी.एच.ई.डी. से और अधिकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु पी.एच.ई.डी. द्वारा इन पदों को पंचायती राज में Ex कैडर के पदों के रूप में स्वीकृत कराने के आदेश चाहे हैं। विभाग द्वारा पीएचईडी को पुनः अनुरोध किया गया है कि पीएचईडी के वर्तमान स्वीकृत पदों में से ही कार्मिक उपलब्ध कराये जावें।	Task Started, but not Completed
58	Aide Memoires of Review Meetings of Women & Child Development, Rural Development, Panchayati Raj Depts dated 29.05.2017.	ODF in Sriganganagar - expedite it.	श्री गंगानगर जिले में कुल 336 ग्राम पंचायतों में से 336 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुकी है।	Implemented

Chief Minister's Information System CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
59	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during Bundi Visit (14.09.2017 to 16.09.2017)	The revalidation and extending the validity period of registration of the pattas issued during the patta campaign should be ensured.	विभागीय अधिसूचना 1457 दिनांक 22.11.2017 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में नियम 167-क जोड़कर प्रावधान किया गया है कि पंचायतें स्वयं के द्वारा पूर्व में जारी किये गये पट्टा या विक्रय विलेख को पुनः विधिमान्य कर सकेगी।	Implemented
60	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during Bundi Visit (14.09.2017 to 16.09.2017)	Optimum utilization of resources in various schemes of Rural Development and Panchayati Raj.	पंचायती राज द्वारा संचालित योजनाओं में प्राप्त निधियों का यथासंभव उपयोग करने हेतु सभी प्रयासकिये जा रहे हैं। शासन सचिव के स्तर से नियमित रूप से पत्र लिखे जा रहे हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव के द्वारा मासिक रूप से विडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा की जाती है। मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा त्रैमासिक रूप से सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा बैठक/चर्चा की जाती है। उपलब्ध मानव संसाधन के अनुसार यथा संभव कार्य निष्पादन के पूर्ण प्रयासकिये जाते हैं। विभिन्न बिन्दुओं पर जिलों को तत्काल मार्गदर्शन/ स्पष्टीकरण भी प्रदान किया जाता है ताकि अस्पष्टता के अभाव में कार्यों की गति बाधित नहीं हो।	Implemented
61	Instructions given by Hon'ble Chief Minister during Review Meeting of Ajmer District dated 10.10.2017.	Those issues pending at the State level to be resolved at the earliest - necessary sanctions to be issued and tenders to be invited.	No issues are pending at the State level of District Ajmer.	Implemented
62	CM Priority Issues	Payment position of Toilets - SBM Rural	Rural SBM Payment status- Out of 56.74 Lac SBM beneficiaries 38.08 Lac have been incentivized and 18.66 lacs are still remaining up to 08.05.2018. MDWS Requested to release Center Share For Rs. 124974.00 Lac vide Later No. 1042 Dated 04.05.2017 By Hon. Minister RD & PRD.	Task Started, but not Completed
63	CM Priority Issues	Putting up additional counters under Nyay Apke Dwar :- • Grievance related to Janta Dal Yojana or	Directions has been issued to accept complaints of JJY and other schemes during Nyay Aapke Dwar program. Orders are being followed and progress is being reported online.	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		those related single phase pumps where the community has filed an affidavit stating that they will make payments		
64	दिनांक 10.06.2015 को झालावाड़ एवं बारां जिले की समीक्षा बैठक के दौरान।	ग्रामीण गौरव पथों के साथ नाली निर्माण आवश्यक रूप से किया जाये। इस हेतु नरेगा सहित सभी संभव विकल्पों पर विचार किया जाकर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाये।	गौरव पथ निर्माण के तहत नाली का आउट फॉल भी दिया जाये। नाली निर्माण एवं इसके आउटफॉल का कार्य जिला परिषद की योजना के तहत कराये जाने के निर्देश राज्य के सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पूर्व में ही दिनांक 09.03.2015 को जारी किये जा चुके हैं।	Implemented
65	Review meeting and Presentation of Rural Development and Panchayti Raj dated 04.01.2014.	All the schools will be provided toilets and their maintenance will be ensured. Suitable system to fill the water tanks of toilets will be ensured to make all the school toilets functional. Similar efforts will be made for Aanganwadi Centres.	Out of 73548 school buildings, 128 schools are without toilets. 1115 toilets are such where separate toilets are not available. Therefore, 1371 schools need to be constructed through SSA for which districts have been instructed accordingly. There are 21407 Aanganwadies and 16208 are running in Government buildings. Out of this, total 37615 Aanganwadies, 20110 have toilets. The coverage is 53.46%. To ensure regular water supply in the schools and Aanganwadies where piped water supply is not available, sum of Rs. 5.00 crores have been transferred from PHED under NRDWP fund to SSA and subsequently to SMCs to equip handpumps with a forced lift pumps. Till date, about 2600 such forced lift pumps have been installed. A provision of Rs. 10000.00 is for school buildings and Rs. 13000.00 for those premises where Aanganwadies are also situated with the schools. Rs. 3744.65 lacs have been provided for O&M of school toilets from Untied Fund to PRIs	Implemented
66	Review meeting and Presentation of Rural Development and Panchayti Raj dated 04.01.2014.	Nirmal Bharat Abhiyaan: This activity will be continued and efforts will be made to make all the villages Open	बेसलाइन सर्वे 2012 की संशोधित सूची के अनुसार 79.29 लाख परिवार शौचालय विहिन थे जिनमें से वर्ष 2013-14 में 2.70 लाख, 2014-15 में 6.49 लाख, वर्ष 2015-16 में 20.90, वर्ष	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		Defecation Free (ODF) in next 5 years.	2016-17 में 27.91 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21.28 लाख शौचालय निर्मित हो चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल 79.29 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। वर्ष 2014-15 में 447, वर्ष 2015-16 में 1348, वर्ष 2016-17 में 3151 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4948, इस प्रकार कुल 9894 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो चुकी है।	
67	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में जिला धौलपुर के भ्रमण के दौरान।	गाँव अमानपुरा में ताल की पाल को पक्की एवं ऊँची कराये जाने के संबंध में प्राप्त ज्ञापन के संबंध में शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये।	गाँव अमानपुरा, पंचायत समिति बसेडी, जिला धौलपुर में ताल की पाल को पक्की एवं ऊँची कराये जाने का कार्य 1.28 लाख व्यय कर पूर्ण किया जा चुका है।	Implemented
68	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में जिला धौलपुर के भ्रमण के दौरान।	चांदपुरा गाँव में शमशान घाट हेतु भूमि आवंटन कराने के संबंध में प्राप्त ज्ञापन में शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। के संबंध में प्राप्त ज्ञापन में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये।	चांदपुरा गाँव जिला धौलपुर में शमशान घाट हेतु भूमि आवंटन कराने के संबंध में ग्राम चांदपुरा तहसील सरमथुरा हेतु खसरा न0. 797 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड को जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 07.08.2014 द्वारा निशुल्क शमशान हेतु भूमि का आवंटन कर दिया गया है।	Implemented
69	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में करौली जिले के भ्रमण के दौरान।	ग्राम बिनेगा तहसील मासलपुर में नलकूप(बोर) चालू कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।	प्रकरण में सचिव की रिपोर्ट दिनांक 17.12.14 के अनुसार ग्राम बिनेगा तहसील मासलपुर जिला करौली में सांसद योजना अन्तर्गत स्वीकृत बोर का बिजली कनेक्शन करवाया जाकर मोटर चालू करवाकर सप्लाई जारी कर दी गई है वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।	Implemented
70	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में करौली जिले के भ्रमण के दौरान।	ग्राम ससेडी में रोड पर जमा पानी के उचित निकास एवं पानी की टंकी के आस पास जल एकत्रीकरण की व्यवस्था की जावे जिससे सडक में पानी के कारण कटाव नहीं हो।	प्रकरण में ग्राम सचिव की रिपोर्ट दिनांक 17.12.14 के अनुसार ग्राम ससेडी में रोड पर जमा पानी को निकालकर रास्ता सही करवा दिया गया है तथा पानी की टंकी के पास जमा पानी को कच्ची नाली बना कर निकलवा दिया गया है। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
71	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में करौली जिले के भ्रमण के दौरान।	मण्डरायल शिकारगंज रोड से तीन बड जाने वाली रास्ते पर भरे हुए कीचड की तुरंत सफाई कर पानी तथा कीचड भराव की समस्या का उचित निदान किया जावे एवं इस बात का ध्यान रखा जावे कि ये समस्या पुनः उत्पन्न नही हो।	तीन बड से शिकारगंज रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग करौली द्वारा राशि 285.21 लाख रुपये की स्वीकृति के तहत 1 किलोमीटर लम्बाई में सीसी सडक का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में सीसी सडक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।	Implemented
72	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में करौली जिले के भ्रमण के दौरान।	ग्राम मांच पंचायत समिति करौली में पुरानी ऐतिहासिक बावडी स्थानीय निवासियों के अनुसार जिसका पूजन किया जाता है, के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव तैयार किया जावे।	ग्राम मांच की ऐतिहासिक बावडी के जीर्णोद्धार हेतु स्वविवेक योजना के तहत राशि 4.60 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है ग्राम पंचायत द्वारा कार्य प्रगतिरत है।	Implemented
73	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में करौली जिले के भ्रमण के दौरान।	महमदपुर सडक पर सफाई एवं पानी के निकास के लिये नालियों की व्यवस्था के निर्देश दिये।	जिला करौली के महमदपुर पंचायत समिति सपोटरा सडक पर सफाई एवं पानी के निकास के लिये नालियों की सफाई करवा दी गई है एवं नियमित रूप से सफाई करवाई जा रही है।	Implemented
74	दिनांक 14.02.2014 को भरतपुर संभाग में करौली जिले के भ्रमण के दौरान।	महमदपुर में पेयजल की समस्या के निदान के लिये नागरिकों की समिति बनाकर जलदाय योजना चलाने पर प्रस्ताव तैयार किया जावे, जिससे नागरिकों को निजी नलकूप से पानी खरीदने के लिये मजबूर नहीं होना पडे। कमेटी बना कर जनता जल योजना में समाधान किया जावे।	प्रकरण में महमदपुर में पेयजल की समस्या के निदान के लिए ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से एक 03 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जो जनता जल योजना का संचालन करेगी तथा पीएचईडी विभाग द्वारा बोरिंग करवा दी है तथा विद्युत कनेक्शन भी हो गया है ग्राम पंचायत द्वारा पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर पेयजल सप्लाई कर दी गई है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
75	दिनांक 23.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान खमनोर जन सुनवाई कैम्प में।	ग्राम पंचायत सेमा में निर्मित मालिदा स्टेडियम का नामकरण महाराणा प्रताप स्टेडियम करने बाबत- प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करे।	जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश दिनांक 30.04.2015 के द्वारा ग्राम पंचायत सेमा पंचायत समिति खमनोर में निर्मित मलीदा स्टेडियम का नामकरण महाराणा प्रताप स्टेडियम ग्राम मलीदा कर दिया गया है।	Implemented
76	दिनांक 18.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान।	Residents demand that the development works carried out at Banjariya village by GP be inspected for quality	गांव बंजारिया में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु जिला स्तर पर जांच दल गठित किया गया। जांच दल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निम्न कार्यवाही कर दी गई है। (1) श्री झाबरमल, ग्राम सेवक पदेन सचिव को ग्राम पंचायत बंजारिया से हटाकर पंचायत समिति, खैरवाडा मुख्यालय में कर दिया है। (2) श्री झाबरमल, ग्राम सेवक पदेन सचिव के विरुद्ध नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। (3) श्रीमती पानु देवी मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत बंजारिया पंचायत समिति खैरवाडा को विभाग के आदेश क्रमांक 3901 दिनांक 17.9.2014 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।	Implemented
77	दिनांक 19.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान।	To be examined- Is it possible to allow upper-caste residents to also contest for Chairmen in PRIs? This was allowed in the past. Pr. Secy RD & PR to examine and put up detailed note	राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 की धारा 3 (ड) में निम्न प्रावधान है:- प्रत्येक पंचायती राज संस्था के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायती राज संस्था में ऐसे समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 13) की धारा 15 और 16 के अधीन आरक्षण दिया जाना ईप्सित है:	Implemented

Chief Minister's Information System CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
			परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल स्थानों के आधे से कम नहीं होगा: परन्तु यह और कि सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे अतः उपरोक्त व्यवस्था लागू होने की वजह से राज्य के पीसा क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित हैं, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य किसी जाति या वर्ग का व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।	
78	दिनांक 20.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान।	GP Paroli Rathore-residents do not wish that their village is brought under Panchayat Samiti Gonera and want it to remain under Panchayat Samiti Ghatol which is just 7 Kms away	चूंकि ग्राम पंचायत गनोरा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण नहीं करने के कारण प्रस्तावित पंचायत समिति गनोरा का नवसृजन नहीं किया गया है।	Implemented
79	दिनांक 20.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान।	<ul style="list-style-type: none"> • Sh Prakash Chand Naik, resident Mungana, the Dhariwad- appeared for competitive exam for 3rd grade teacher organized by Zilla Parishad in 2012. Instead of OMR sheet B he used OMR Sheet C. Matter is to be enquired into and findings brought before CM 	<ul style="list-style-type: none"> • Report given by the examination conducted agency is as follows:- • "We have examined the case and found that the candidate has written his booklet No in his OMR answer sheet as 3530144 accordingly his answers were check with the answer keys of series 3 keys (since first digit of the booklet no. represents the series of question booklet) and marks were awarded accordingly. His answers also checked manually using answer keys of series 3 and found his marks matches with that given in his result". 	Implemented
80	दिनांक 21.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान।	<ul style="list-style-type: none"> • Mohandevi d/o Keshuram. Appointed as Pracheta in 1985 by District Women Development Agency (DWDA) Udaipur in 1985. • DWDA was 	<ul style="list-style-type: none"> • Smt. Mohandevi d/o Keshuram. Appointed as Pracheta in 1985 by District Women Development Agency (DWDA) Udaipur in 1985 and she was posted in Udaipur District till 29.08.2007. • After 29.08.2007 she was posted in district Chittorgarh. • After formation of district Pratapgrah her service were tranfered to 	Implemented

Chief Minister's Information System CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		<p>merged into Zilla Parishad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Complainant served for 29 years and 6 months. Not receiving any pension or related benefits 	<p>District Pratapgrah and she was retired on 30.06.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Women empowered has informed that women working on the post of Precheta are not entitiled for pension. The merger of District Women Development Agency (DWDA) into the ZilaParishad is under process. Next action would be taken by DWDA. 	
81	दिनांक 23.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान।	<p>Piplantri GP - Watershed Management -</p> <ul style="list-style-type: none"> Appreciable work on watershed and rural development through convergence of various government schemes. Striking reclamation of mining waste dump Pr. Secy RD & PR and Secretary Irrigation to visit. Use the watershed managers and social capital developed here as resources to help replicate this initiative locally and in other parts of the state The request for a Training Centre to be considered on priority 	<p>जिला राजसमन्द के पीपलांत्री गांव में जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण की 170.40 लाख की स्वीकृति जारी कर प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त भवन में फर्नीचर, कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, विद्युत सप्लाई, आर ओ प्लांट चारदीवारी, सी.सी. पेवमेट, एलीवेशन, लेवलिंग, पानी सप्लाई, सौर उर्जा चलित प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि कार्यो के लिए राशि 144.18 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसके तहत उपरोक्त सभी कार्य किये जा रहे है।</p>	Task Started, but not Completed
82	दिनांक 23.08.2014 को उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान।	<p>To Change the name of Malida Stadium at gram Panchayat Sema as "Maharana Pratap Stadium" Pr. Secretary RD & PR to enquire and do necessary action.</p>	<p>जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश दिनांक 30.04.2015के द्वारा ग्राम पंचायत सेमा पंचायत समिति खमनोर में निर्मित मलीदा स्टेडियम का नामकरण महाराणा प्रताप स्टेडियम ग्राम मलीदा कर दिया गया है।</p>	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
83	दिनांक 08.10.2014 को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान।	Chief Secretary to hold a meeting related to implementation of Mid-Day meal programme after the integration of Schools/rationalisation of teachers.	मिड डे मिल योजना की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित। जिसमें एकीकरण के पश्चात विद्यालयों की वास्तविक संख्या, विद्यार्थियों का नामांकन एवं कुक कम हैल्पर्स की वास्तविक संख्या का आकलन कर, योजना की गतिविधियों एवं व्यवस्थाएं उसके अनुसार ही सम्पादित की जावे। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के एकीकरण के संबंध में राज्य के समस्त विद्यालयों में मिड डे मील योजना के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।	Implemented
84	दिनांक 08.10.2014 को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान।	The issue of withdrawal of SLP from Supreme Court needs to be taken up on priority.	उक्त एसएलपी में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) के प्राप्तियों में न्यूनतम उत्तीर्णों में दी गई छूट के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामधन कुमावत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 की पालना में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 का पुनः संशोधित परिणाम जारी कर विज्ञापित पदों पर पुनः संशोधित वरियातानुसार पात्र अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही वर्तमान में संबंधित जिला परिषदों द्वारा की जा रही है। जिला परिषदों द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर लिया गया है।	Implemented
85	सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 21.09.2014 से 22.09.2014 को झालावाड़ जिले के दौरे के दौरान दिये गये निर्देश।	जनता जल योजना के सभी 81 कनेक्शनों का निरीक्षण कर योजना के विद्युत बिलों के बकाया भुगतान के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित जनता जल योजना के व्यय का पूर्ण भुगतान राज्य वित्त आयोग से करने हेतु आदेश दिनांक 30.03.2015 को जारी किये जा चुके हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर विद्युत बिलों का भुगतान न करने की दशा में विकास अधिकारी को भुगतान करने के लिये अधिकृत कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 की बजट धोषणा में बंद जनता	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
			जल योजनाओं को पुनः चालू करने हेतु राशि का प्रावधान किया गया है जिसकी क्रियान्विति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जानी है।	
86	सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 21.09.2014 से 22.09.2014 को झालावाड़ जिले के दौरे के दौरान दिये गये निर्देश।	जिला परिषद् की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	-	Implemented
87	सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.09.2014 को झालावाड़ जिले में फील्ड विजिट के दौरान दिये गये निर्देश	दीवडी के ग्रामीणों को पट्टे दिलवाने की कार्यवाही की जाये।	दीवडी के ग्रामीणों को पट्टे दिलवाने की कार्यवाही हेतु विभागीय पत्र दिनांक 09.06.2015 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़ को निर्देशित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़ ने अवगत करवाया है कि दीवडी में कुल परिवारों की संख्या 161 है जिसमें से 26 पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं तथा 82 परिवारों को अभी और पट्टे जारी कर दिये गये हैं। शेष परिवार जो चारागाह एवं कृषि भूमि पर मकान बना कर रह रहे हैं उनको नियमानुसार पट्टे जारी किया जाना संभव नहीं है।	Implemented
88	सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24.12.2014 को बारां जिले के प्रवास के दौरान दिये गये निर्देश	हैण्डपम्प खराब होने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर की जानकारी अधिक से अधिक लोगों व जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाये। पंचायत चुनाव, 2015 के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित कर इस टोल फ्री नम्बर के बारे में जानकारी उपलब्ध करायें।	महानिदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर को नव निर्वाचित सभी जन प्रतिनिधियों एवं अन्य को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में अवगत कराये जाने बाबत विभागीय पत्र दिनांक 23.02.2015 द्वारा हैण्डपम्प खराब होने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। सभी जिला कलक्टरों, मुख्य / अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को भी दिनांक 23.02.2015 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
89	सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24.12.2014 को बारां जिले के प्रवास के दौरान दिये गये निर्देश	राज्य में निर्मित किये जाने वाले ग्रामीण गौरव पथों हेतु एक एम.आई.एस.टूल विकसित किया जाकर प्रक्रियाबद्ध रूप से इन सड़कों का निर्माण कराया जाये। इनकी मॉनिटरिंग ब्लॉक लेवल पर पंचायतों को गोद लिया है, उन्हीं अधिकारियों से करवाई जावे। संबंधित सरपंच के सन्तुष्ट होने पर ही कार्य का भुगतान किया जावे। गौरव पथ निर्माण के तहत नाली का आउट फॉल भी दिया जाये। नाली निर्माण एवं इसके आउटफॉल का कार्य जिला परिषद की योजना के तहत कराया जाये।	राज्य के सभी जिलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उक्त निर्देशों की शतप्रतिशत क्रियान्वित सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 09.03.2015 को पत्र लिखा गया है।	Implemented
90	नवनिर्मित जिला प्रमुखों एवं प्रधानों की बैठक दिनांक 24.03.2015	नवनिर्वाचित जिला प्रमुखों एवं प्रधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जावे।	नवनिर्वाचित जिला प्रमुखों एवं प्रधानों को पंचायती राज संबंधी नियमों एवं कार्यों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री/माड्यूलस तैयार किये जा चुके हैं। प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु लगभग 4.00 करोड की राशि इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर को अनुमत की गई है। प्रथम चरण में सभी संस्था अध्यक्षों, प्रमुख/प्रधान/सरपंच का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया जा चुका है जिसमें दिनांक 27-28/07/2015 को जिला प्रमुखों का एवं दिनांक 14-15/09/2015 को प्रधानों का प्रशिक्षण आयोजित करवाया जा चुका है।	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
91	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 20.12.2014 को आदर्श ग्राम योजना के संबंध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश।	पंचायत दिवस में रिकार्ड अपडेशन, अचल सम्पत्ति व लाभार्थी का सत्यापन सुनिश्चित करें तथा पंचायत राज के पुराने रिकार्ड का डिजिटाइजेशन किया जावे।	पंचायत दिवस कार्यक्रम के जारी आदेश दिनांक 13.05.2014 द्वारा रिकॉर्ड अपडेशन, अचल संपत्ति एवं निजी लाभ योजना में लाभान्वितों का भौतिक सत्यापन किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत दिवस कार्यक्रम के दो चरण पूर्ण हो चुके हैं। पंचायती राज के पुराने रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन का कार्य करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।	Task Sanctioned, but not Started
92	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 20.12.2014 को आदर्श ग्राम योजना के संबंध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश।	ओडीएफ के तहत जिन जिला कलेक्टरों ने अच्छा काम किया है उन्हें प्रोत्साहित करें एवं अन्य जिला कलेक्टरों को भी प्रोत्साहित करने हेतु ओडीएफ की कार्यशाला शीघ्र आयोजित की जावे।	विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों की माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 23/07/2015 को कॉन्फ्रेंस आयोजित करवायी जा चुकी है। जिसमें ओडीएफ के तहत अच्छा काम करने वाले जिला कलेक्टरों में जिला उदयपुर एवं बीकानेर का प्रस्तुतिकरण कराया गया।	Implemented
93	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 20.12.2014 को आदर्श ग्राम योजना के संबंध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश।	प्रत्येक जिला कलेक्टर, लाईन विभागों एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किये गये कार्यों की मासिक समीक्षा करें तथा समीक्षा के दौरान आ रही शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, जिससे कि राज्य स्तर पर अनावश्यक कार्य नहीं आये और कार्य में देरी न हो।	सभी जिला कलेक्टरों को लाईन विभागों एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किये गये कार्यों की मासिक समीक्षा करने एवं इस दौरान प्राप्त शिकायतों का अविलंब शत प्रतिशत निस्तारण किये जाने हेतु पत्र दिनांक 21.04.2015 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	Implemented
94	सचिव मुख्यमंत्री द्वारा जिला झालावाड़ में दिनांक 15-02-2015 को दिये गये निर्देश	गौरव पथ कार्यों में श्रम सामग्री मद का अनुपात निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार 60:40 नहीं होने से इन कार्यों को अनुमत करने हेतु अथवा अधिक राशि	गौरव पथ का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। गौरव पथ कार्यों में अधिक राशि (श्रम सामग्री) हेतु नरेगा अथवा चौदहवें वित्त आयोग/ राज्य वित्त आयोग/ पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बंध राशि आदि योजनाओं से कन्वरजेंस/ डवटेल करते हुए कार्य शीघ्रता से पूर्ण करवाये	Implemented

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
		कन्वरर्जेंस/ डब टेल के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग से उपलब्ध करवाये जाने हेतु जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा पंचायतीराज विभाग को पत्र लिखा गया है तथा प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लिया जावे।	जाने हेतु जिला कलक्टर झालावाड़ को पत्र दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	
95	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.05.2015 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देश।	स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की प्रगति की मासिक समीक्षा की जावे इसमें जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाकर समस्त जिला कलक्टर प्रभावी कार्यवाही करें।	स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाती है तथा जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। जो समय-समय पर स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा करती है।	Implemented
96	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.05.2015 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देश।	स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों की थर्ड पार्टी निरीक्षण की कार्यवाही की जावे।	सम्पूर्ण पंचायत खुले में शौच से मुक्त होने पर निर्मित शौचालयों का अन्तजिला टीम गठित कर सत्यापन/निरीक्षण कराया जाता है।	Implemented
97	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.05.2015 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देश।	जनता जल योजना में सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।	जनता जल योजनाओं के समस्त व्यय का भुगतान अनुदान राशि से करने के आदेश जारी। मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 05.02.2016 के निर्णयानुसार जनता जल योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा किये जाने एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य स्तर पर आवश्यक कार्मिक पी.एच.ई.डी. द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्रावली अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की	Task Started, but not Completed

Chief Minister's Information System
CM Directions

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
			<p>अध्यक्षता में दि० 17.07.2017 को बैठक आयोजित की गई जिसमें पी.एच.ई.डी. से और अधिकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु पी.एच.ई.डी. द्वारा इन पदों को पंचायती राज में Ex कैडर के पदों के रूप में स्वीकृत कराने के आदेश चाहे हैं। विभाग द्वारा पीएचईडी को पुनः अनुरोध किया गया है कि पीएचईडी के वर्तमान स्वीकृत पदों में से ही कार्मिक उपलब्ध कराये जावें।</p>	
98	<p>माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.05.2015 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देश।</p>	<p>पंचायतीराज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जावे।</p>	<p>राज्य स्तर पर सभी जिला प्रमुख/प्रधान का प्रशिक्षण आयोजित करवाया जा चुका है। जिला स्तर पर सभी सरपंचगणों का प्रशिक्षण माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2015 को आयोजित करवाया जा चुका है।</p>	Implemented
99	<p>माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.05.2015 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देश।</p>	<p>Swachh Bharat Mission - Action be taken to ensure behavioral change.</p>	<p>1. पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की आदतों में व्यवहारगत परिवर्तन के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाना है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति के स्वयं के घर में स्वच्छ शौचालय है तथा उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इस शौचालय का उपयोग किया जा रहा है, वही व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा। इस आदेश के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 4 लाख 78 हजार जन-प्रतिनिधियों के यहां शौचालयों का निर्माण हुआ है।</p> <p>2. राज कर्मचारियों के साथ मानदेय पर कार्य करनेवाले कार्मिक ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे इसलिए उनमें भी व्यवहारगत परिवर्तन जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित कर्मचारियों /निश्चित मानदेय प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं/उचित मूल्य के दूकानदार/रूपये</p>	Implemented

**Chief Minister's Information System
CM Directions**

Sr. No.	Meeting/Visit Description	Direction Details	Action Taken by Dept	status
			<p>50000 से अधिक कृषि ऋण लेने वाले किसानों के निजी घरों में शौचालय की उपलब्धता और उसके परिवार द्वारा उपयोग किया जाना अनिवार्य किये जाने फलस्वरूप राज्य में 15 लाख परिवारों में व्यवहारगत परिवर्तन होगा एवं उनके घरों में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।</p> <p>3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी आदतों में परिवर्तन लाने हेतु सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुविधाओं की सुलभता हो, इस हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक सरकारी कार्यालय में कम से कम एक शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।</p> <p>4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) के तहत राज्य में औद्योगिक घरानों के कार्यक्षेत्र के आस पास की ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले लोगों की आदतों में व्यवहार गत परिवर्तन के लिए कार्य किये जा रहे हैं। हिन्दूस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अजमेर , भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द एवं उदयपुर में कार्य किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा अगले 3 वर्षों में कुल 384 करोड़ व्यय किया जान प्रस्तावित है। इसके अलावा केयर्न एनर्जी , वांडर सीमेंट द्वारा भी इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।</p>	
100	माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.05.2015 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देश।	I.T. enablement of Panchayat Raj Department be undertaken. Panchayat level plans be brought on e-Platform.	A set of applications called PES applications (Panchayat Enterprise Suite) was developed by NIC, New Delhi under the guidelines of Ministry of Panchayati Raj, Government of India, New Delhi. Under GPDP, PR department has incorporated 97% Panchayat plans of Financial Year 2016-17 and 94% Panchayat plans of Financial Year 2015-16 on E-platform (Planplus module in PES). The activity is continuous in nature and implemented every year.	Implemented